सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-274 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, रविवार 08 जून , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और भागीरथी पहल साबित होगा 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान

जयपुर। जल ही जीवन है। सदियों से जल की उपलब्धता और उपयोग मानव सभ्यता के अस्तित्व और विकास के क्रम से जुड़ा हुआ है। 'जल है तो कल है'- इस कथन का महत्व सबसे अधिक राजस्थानवासी समझते हैं क्योंकि बूंद-बूंद का संचय और संरक्षण यहां की धरोहर भी है और जरूरत भी। मौजूदा समय में राजस्थान की ऐतिहासिक जल संस्कृति की इस विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा भगीरथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उठाया है। राजस्थान में गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर प्रकृति के दो महत्वपूर्ण तत्वों जल और पेड़ के लिए विशेष अभियान की शुरूआत की गई। जयपुर के रामगढ़ बांध पर मुख्यमंत्री द्वारा श्रमदान के साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान का आगाज हुआ। साथ ही, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और इससे जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया।

मुख्यमंत्री के विजन से 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान के जरिये सभी जिलों में 5 जून से 20 जून तक जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरूद्धार के कार्यों की शुरूआत हुई है। वहीं इसे जन-अभियान बनाने के लिए वंदे गंगा कलश यात्रा तथा जलाशय पूजन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें आमजन को जल संरक्षण का महत्व बताकर जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश के भूजल स्तर को बढ़ाने में और बारिश में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी के संचय में मददगार साबित होगा। प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में पहले भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं। कर्मभूमि से मातृभूमि

अभियान के माध्यम से चार साल में लगभग 45 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। हरित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ने 5 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आमजन से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मानसून में एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के पहले ग्रीन बजट से प्रदेश स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ धरा की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 11 ई-वेस्ट संग्रहण वाहन, सी.ई.टी.पी. सांगानेर लोकार्पण, राज्य के 6 बड़े अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण, पांच लव कुश वाटिकाओं, उदयपुर में माछला मगरा नगर वन व रिसाला ग्रीन लंग्स और जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी, सर्कुलर इकोनॉमी इन्सेंटिव स्कीम और मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 की शुरूआत की सौगात दी। यह सभी कार्य मुख्यमंत्री की पर्यावरण हितैषी सोच एवं नीतियों का प्रतिबिम्ब हैं।

प्रदेश में 5 जून को ही आयोजित हुए अन्य कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी के केशोरायपाटन में केशव घाट पर चम्बल मां (चर्मण्यवती नदी) की मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने हमारी संस्कृति को जल संरक्षण से जोड़ते हुए चुनरी महोत्सव में शिरकत की। उनके द्वारा अर्पित की गई चुनरी को नाव और बोट्स द्वारा चम्बल नदी पर केशव घाट से रंगपुर घाट तक ले जाया गया। श्री केशवराय मंदिर में पुजारियों द्वारा मुख्यमंत्री को जल संरक्षण के इस अभियान के लिए अभिनंदन पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री ने बूंदी जिले के केशोरायपाटन में आयोजित कार्यक्रम से पहले संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के विभिन्न कॉम्पोनेंट्स का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन ईसरदा बांध, नवनिर्मित नवनेरा बैराज और चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट के निर्माण कार्यस्थलों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशहरा व विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भरतपुर में गंगा माता मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को गंगाजल, तुलसी के पौधे और प्रसाद का वितरण किया। इसके बाद उन्होंने बिहारी जी मंदिर में भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन अभियान बनाने के लिए भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा-पाठ कर दीपदान किया।

20 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत आगामी दिनों में नए जल संग्रहण एवं जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों का शुभारंभ, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत हुए कार्यों का लोकार्पण एवं नए कार्यों की स्वीकृति, जोहड़ बावड़ी तथा अन्य जल स्रोतों की साफ-सफाई, पौधारोपण अभियान, पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति विभिन्न जन-जागरूकता अभियान एवं जल संरक्षण पर कार्यशाला सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर प्रदेश के आमजन, किसानों और उद्योगों की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रभावी निर्णयों और दूरगामी सोच से राज्य सरकार ने डेढ़ साल में रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास परियोजना, माही बांध, सोम-कमला-अंबा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में जल संचयन तथा संरक्षण को बढ़ावा दिया है।

गुर्जरों का अल्टीमेटम-कागज सौंपूंगा और फिर मंत्रालय बांटूंगा- विजय बैसला की सरकार को दो टूक

बयाना/भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना मे एमबीसी आरक्षण और देवनारायण योजना में खामियों को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर रविवार को बयाना के पीलूपुरा गांव स्थित शहीद स्मारक स्थल पर गुर्जर समाज द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।

शनिवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने महापंचायत स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों से महापंचायत में आने वाले लोगों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।

बैसला बोले- सिर्फ कागजों में है 5% आरक्षण

विजय बैसला ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया 5ब एमबीसी आरक्षण केवल कागजों तक सीमित है। समाज को इसका वास्तविक लाभ केवल 1.5 से 2 प्रतिशत ही मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में आरक्षण की प्राथमिकता तय करने की बात कही गई थी – पहले जनरल, फिर ओबीसी और फिर एमबीसी – लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा।

देवनारायण योजना पर भी उठे सवाल

बैसला ने कहा कि 17 साल के संघर्ष में दो चीज मिली है 5ब आरक्षण 2019 में और देवनारायण योजना देवनारायण योजना भी खट्टे में पड़ी है देवनारायण योजना का लाभ समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है। न तो बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं और न ही एडमिशन में पारदर्शिता दिखाई दे रही है। उन्होंने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने में भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और चेताया कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो समाज महापंचायत में बड़ा निर्णय ले सकता है। उन्होंने समाज के लोगों की छोटी पंचायत में आज कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा 11:00 बजे तक पहुंच जाना मैं समाज की तरफ से एक कागज का टुकड़ा प्रशासन के नुमाइशों को सौंप दूंगा उसके बाद 1:00 बजे से मैं मंत्रालय बांटना शुरू कर दूंगा सड़क मंत्रालय रेल मंत्रालय और खाना मंत्रालय एक-एक रोड पर आदमी होगा चाहे दौसा हो या सिकंदरा किसी को नहीं छोड़ेंगे हम।

गुर्जर समाज की प्रमुख मांगें-

1. एमबीसी आरक्षणनको संविधान की नौवीं अनुसूचीमें शामिल किया जाए।
2. 2019 आंदोलन के दौरान किए गए समझौतों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
3. 5% आरक्षण का समान और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए।
4. देवनारायण योजना का लाभ वास्तव में वंचित और योग्य छात्रों को दिया जाए।
5. आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे बिना शर्त वापस लिए जाएं।
6. आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

राजस्थान का हेल्थ मॉडल भाजपा सरकार ने कर दिया बर्बाद-गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मौजूदा हेल्थ सिस्टम पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए

कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हेल्थ मॉडल को भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया।

प्रदेश की जनता कर रही है अफसोस

अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ङ्क पर लिखा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश-दुनिया में चर्चा का विषय बना था परन्तु भाजपा सरकार ने इसे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अफसोस कर रही है कि ऐसी अकर्मण्य सरकार का अभी आधे से अधिक कार्यकाल बाकी है। इस समय में प्रदेश की कितनी दुर्गति होगी।

प्रदेश की लगभग हर योजना की स्थिति खराब

अशोक गहलोत एक अन्य मामले में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार जरूरतमंद अनाथ बालकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही जिससे यह मासूम भीख मांगने को मजबूर हैं। लगभग हर योजना की ऐसी ही स्थिति बन गई है।

कांग्रेस सरकार में चलाई गई थी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

कांग्रेस सरकार के दौरान कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना चलाई गई। इस योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बच्चों को तत्कालिक सहायता के रूप में राशि रुपए 1.00 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक राशि रुपए 2500/- प्रतिमाह एवं राशि रुपए 2000/- वार्षिक देय है।

जिला कलेक्टर, सीकर से अनुरोध

इसके अलावा प्रत?येक अनाथ बच?चों के लिए पालनहार योजना में 5 वर्ष की आयु तक के बच?चे के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा स?कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपए प्रतिमाह की राशि देय है। जिला कलेक्टर, सीकर इन बच्चों को इन दोनों योजनाओं में से नियमानुसार लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें।

अशोक गहलोत से मिलने घर पहुंचे सचिन पायलट

जयपुर। राजस्थान की सियासत में आज एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता और डूष्टष्ट महासचिव सचिन पायलट पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर स्थित सिविल लाइंस सरकारी आवास पर पहुंचे। बता दें, यह मुलाकात स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के सिलसिले में हुई।

दरअसल, 11 जून को दौसा के पास भंडाना-जीरोता में स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। यह सभा राजेश पायलट स्मारक पर होगी, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। इस अवसर

पर सचिन पायलट, उनकी मां रमा पायलट और पायलट परिवार के अन्य सदस्यों के साथ-साथ कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इस बार 25वीं पुण्यतिथि होने के कारण यह आयोजन विशेष होगा। बता दें, राजेश पायलट का 25 वर्ष पहले दौसा-जयपुर मार्ग पर भंडाना में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। दौसा पायलट परिवार की कर्मस्थली और चुनावी क्षेत्र रहा है, जहां से राजेश पायलट लंबे समय तक सांसद रहे। वे केंद्र में गृह राज्य मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उनका मशहूर नारा 'राम राम सा' आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुलाकात के बाद कहा कि, डूष्टष्ट महासचिव सचिन पायलट ने आवास पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. श्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं और राजेश पायलट जी 1980 में पहली बार एक साथ ही लोकसभा पहुंचे एवं लगभग 18 साल तक साथ में सांसद रहे। उनके आकस्मिक निधन का दुख हमें आज भी बना हुआ है। उनके जाने से पार्टी को भी गहरा आघात लगा।

गौरतलब है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से सियासी तनाव रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, तब कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद डेढ़ साल में ही दोनों नेताओं के बीच मतभेद गहरे हो गए।

वहीं, हर साल राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर भंडाना में होने वाले आयोजन में अशोक गहलोत और उनके समर्थक आमतौर पर शामिल नहीं होते। लेकिन इस बार सचिन पायलट के निमंत्रण और गहलोत के आवास पर मुलाकात के बाद सबकी नजर इस आयोजन पर होगी। यह मुलाकात राजस्थान कांग्रेस में एकता के संदेश के रूप में देखी जा रही है। क्या यह मुलाकात दोनों नेताओं के बीच सियासी दूरियों को कम करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

सवाई माधोपुर CMHO ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा संस्थापन अधिकारी

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तैनात संस्थापन अधिकारी भूपेन्द्र विहारी शर्मा को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने परिवादी से उसके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही को खत्म करने के एवज में रिश्वत मांगी थी।

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले रिश्वत मांग की पुष्टि की

और फिर जाल बिछाकर शुक्रवार को यह कार्रवाई की। आरोपी ने परिवादी को अपने कार्यालय में बुलाया और जैसे ही उसने 25 हजार रुपए की रिश्वत ली, एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश देकर अधिकारी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि भी बरामद हुई है।

एसीबी के डीजी डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि शिकायत मिलने पर भरतपुर रेंज के एसीबी उपमहानिरीक्षक राजेश सिंह की निगरानी में सवाई माधोपुर इकाई के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने यह ट्रैप कार्रवाई की।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी अधिकारी से पूछताछ जारी है और जल्द ही अन्य तथ्य भी सामने आने की उम्मीद है।

MBC वर्ग की विशाल महापंचायत को लेकर राजौर ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

मीनेश चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

जयपुर। राजस्थान प्रदेश में स्वष्ट वर्ग की काफी वर्षों से लंबित चली आ रही मांगों को लेकर कल 8 जून पीलूपुरा-कारवाडी में प्रस्तावित विशाल महापंचायत के संबंध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी मदन मोहन राजौर ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को 8 सूत्रीय मांगों के बारे में पत्र भेजकर कर अवगत कराया।

सरकारों के साथ हुए समझौते आज दिनांक तक लागू नहीं।

गौरतलब है कि मदन मोहन राजौर ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भेजें 8 सूत्रीय मांगों वाला अपने आपमें काफी महत्वपूर्ण है। राजौर के पत्र के अनुसार प्रदेश में स्वष्ट वर्ग (गुर्जर बंजारा राईका लोहार और रैवारी जाति शामिल हैं) की कुछ मांगे और पूर्ववर्ती सरकारों के साथ हुए समझौते आज दिनांक तक लागू नहीं हो पाये है जिनमें से कुछ मांगे एमबीसी वर्ग के उत्थान के लिए अतिमहत्वपूर्ण और अतिआवश्यक है जिनको लेकर कल से संपूर्ण स्वष्ट वर्ग विशाल महापंचायत का आयोजन होने के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

देवनारायण योजना, एमबीसी 5ब आरक्षण को 9वीं अनुसूची शामिल, न्यायिक सेवाओं में बैकलॉग जैसी 8 मागों वाला पत्र।

आपको बता दे, मदन मोहन राजौर में अपने पत्र के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रोस्टर प्रणाली बदली जाए ताकि आरक्षण राजस्थान के स्तर पर होने से आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। इसी प्रकार एमबीसी 5ब आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री एमबीसी समाज के नेताओं को विश्वास में लेकर कैबिनेट अप्रूवल कराकर इसकी सिफारिश केंद्र सरकार के पास

भेजें। ऐसे ही आरक्षण आंदोलन का एक भी केस वापस नहीं लिया। जमीन कुर्की के आदेश भी निकाले गए हैं। केस वापस लिए जाएं। पत्र के तीसरे बिन्दु में आरक्षण आंदोलन का एक भी केस वापस नहीं लिया। जमीन कुर्की के आदेश भी निकाले गए हैं। केस वापस लिए जाने की मांग की गई हैं। ठीक इसी प्रकार देवनारायण योजना का क्रियान्वयन ठीक नहीं होने से पिछले 17 महीने से योजना ठप है। जिससे न स्कूटी मिल रही न छात्रवृत्ति । योजना की मासिक समीक्षा बैठक फिर शुरू की जाने की मांग उठाई गई। पत्र की पांचवीं मांग के अनुसार रूप में बीते 6 साल की बची हुई नौकरियां एमबीसी को देने और राज्य सरकार ने जोधपुर हाईकोर्ट में लिखित में कहा कि एमबीसी आरक्षण जनरल, फिर ओबीसी और अंत में एमबीसी वर्गों को देने की बात कही थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। ठीक इसी प्रकार राजस्थान न्यायिक सेवाओं में बैकलॉग अभी लागू नहीं किया। 2022 से अब तक की आरजेएस वैकेंसी में अब दिए जाने सहित आरक्षण आंदोलन में शहीदों के परिवारों को अनुकंपा नौकरी और मुआवजा शीघ्र ही दिए जाने के साथ सरकारों से हुए समझौतों की पालना हो, सभी लंबित नौकरियां देने का मुद्दा गर्म जोशी के साथ उठाया गया।

डबल इंजन की सरकार होने से आशा और भी बढ़ना स्वाभाविक

पत्र के अंत में, भारतीय किसान यूनियन के नेता मदन मोहन राजौर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब जबकि केन्द्र व राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है जिससे आशा और भी अधिक बढ जाती है कि एमबीसी समाज को नवीं अनुसूची में जोड दिया जावेगा एवं अन्य वर्गों की भाँति अन्य सुविधाएँ राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अन्य लम्बित मामलों में भी उचित सुनवाई की जाने के साथ करबद्ध आग्रह किया गया कि एमबीसी आरक्षण को नवीं अनुसूची में जोडा जाये जिससे इन समाजों के शैक्षिणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास को गति प्रदान की जा सके।

मील का पत्थर साबित हो सकता है मदन मोहन का पत्र

जी हां, यह कहना गलत ना होगा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता मदन मोहन राजौर का सरकार के डैमेज कंट्रोल के रूप में किसी बड़े आंदोलन को रोकने के लिए पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान सरकार मदन मोहन राजौर के पत्र को अमालीगामा पहनता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल यदि समय रहते हुए राजस्थान सरकार मदन मोहन राठौर के पत्र पर गौर करती है तो किसी बड़े आंदोलन को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा।

वैश्विक स्तरपर अब मिलिट्री संघर्ष का आधार ड्रोन वार होने की संभावना - यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब से दुनिया सतर्क

पर्ल हार्बर हमले को अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की वजह माना जाता है।हालांकि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के पीछे बड़ी ताकतों का हाथ होगा?परंतु यहां सवाल यह है खड़ा होता है कि यह 117 ड्रोन ऑपरेटर सहित रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक घुसने और पांच हवाई ठिकानों के पास पहुंचकर रिमोट से 41 बॉम्बर्स जेट्स को उड़ा दिया व रूस को पता ही नहीं चला। बता दें रिमोट का उपयोग ड्रोन के 20 किलोमीटर के दायरे से किया जा सकता है जो रूस की भारी सुरक्षा चूक का नतीजा हो सकता है,जिसका पूरी दुनियाँ को स्वतः संज्ञान लेकर, सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद करना जरूरी हो गया है।

(लेखक - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ में गुटबाजी युद्ध के दौर में नई-नई हैरत अंगेज युद्ध रणनीतियों को देखकर अपने आपको पूर्ण विकसित देशों की श्रेणी में रखने वाले देश भी आज दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब (मकड़ी का जाल) को आखिर अपने अंजाम तक पहुंचनें में रूस जैसा पूर्ण विकसित देश अपनी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है कि 117 ड्रोन रूस की सीमा में करीब 4000 किऱ्मी से अधिक तक अंदर में घुसकर पांच हवाई ठिकानों के 41 बमबर्स जेट तबाह कर सकता है, मेरे जैसा सामान्य आदमी तो यह बात सपने में भी नहीं सोच सकता, इसकी तुलना अब 1941 के पर्ल हार्बर अटैक से की जा रही है।यूक्रेन के ड्रोन अटैक को पर्ल हार्बर अटैक से जोड़ा जा रहा है। इस हमले में जिस तरह यूक्रेन ने रूस को चौंकाया है, उसी तरह से 1941 में जापान ने अमेरिका को अपने हमले से चौंकाया था। दिसंबर, 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में एक आश्चर्यजनक हवाई हमला करते हुए अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को तबाह किया था। इस हमले में 2,403 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। पर्ल हार्बर हमले को अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की वजह माना जाता है।हालांकि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के पीछे बड़ी ताकतों का हाथ होगा?परंतु यहां सवाल यह है खड़ा होता है कि यह 117 ड्रोन ऑपरेटर सहित रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक घुसने और पांच हवाई ठिकानों के पास पहुंचकर रिमोट से 41 बॉम्बर्स जेट्स को उड़ा दिया व रूस को पता ही नहीं चला। बता दें रिमोट का उपयोग ड्रोन के 20 किलोमीटर के दायरे से किया जा सकता है जो रूस की भारी सुरक्षा चूक का नतीजा हो सकता है,जिसका पूरी दुनियाँ को स्वतः संज्ञान लेकर, सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद करना जरूरी हो गया है। चूँकि अब वैश्विक स्तरपर मिलिट्री संघर्ष का आधार ड्रोन वार हो सकता है, यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब से दुनियाँ सतर्क हो गई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,यूक्रेन ने रूस के घर में 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर ऑपरेशन स्पाइडर वेब को सफल अंजाम देने से पूरा विश्व हैरान,18 महीनों का प्लान, 117 ड्रोन से 41 बॉमर्स जेट तबाहकर दिया!

साथियों बात अगर हम दिनांक 1 जून 2025 को यूक्रेन द्वारा रूस के घर में 4 हज़ार किलोमीटर अंदर घुसकर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के क्रियान्वयन को समझने की करें तो,रविवार को रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से जारी जंग में एक नया मोड़ आया, जिस यूक्रेन के बारे में सब कहते थे कि वह अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर जंग लड़ रहा है, उसने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के साथ ही सबका मुंह बंद कर दिया।यूक्रेन के ड्रोन ने दुश्मून के घर में घुसकर उसके 40 बॉम्बिर्स जेट्स पूरी तरह से खत्म कर दिए है,मीडिया न्यू ज की मानें तोयूक्रेन ने इस पर्लहार्बर मोमेंट के साथ ही रूस को दो अरब डॉलर से भी ज्यामदा की चोट पहुंचाई है, यूक्रेन का यह ड्रोन हमला भारत की तरफ से पाकिस्तापन के खिलाफ की गई कार्रवाई अभियान ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ है, ऐसे में भारत भी इससे बड़े सबक सीख सकता है क्योंकि अब जंग का मैदान तेजी से हर पल बदल रहा है।यूक्रेन ने रूस के चार बड़े एयरबेस पर ड्रोन अटैक किए थे, जिसमें पहला था ओलेन्या एयरबेस जो यूक्रेन की सीमा से 1800 किलोमीटर दूर मौजूद है,दूसराहै इवानावो एयरबेस, यूक्रेन की सीमा से इस टारगेट की दूरी 1 हजार किलोमीटर है,टारगेट किए गए तीसरे एयरबेस का नाम है डिगिलेव जो यूक्रेनी बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर मौजूद है और चौथे एयरबेस का नाम है बेलाया, जो यूक्रेनी बॉर्डर से चार हजार तीन सौ किलोमीटर दूर है। पिछले तीन सालों से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में सैकड़ों मौकों पर ड्रोंस का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ये पहली बार था जब कोई ड्रोन 4 हजार किलोमीटर दूर तक चला गया हो। अब सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन 4 हजार किलोमीटर दूर चले गए और रूस के एयर डिफेंस या राडार को खबर भी नहीं लगा ऐसा कैसे संभवहो सकता है?

साथियों बात अगर हम ऑपरेटरों सहित 117 ड्रोन को 4000 किलोमीटर अंदर तस्करी से रूस में पहुंचने को समझने की करें तो,कैसे दिया गया ऑपरेशन को अंजाम?,यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मीडिया बताया है कि इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए 117 ड्रोन के साथ ड्रोन ऑपरेटरों की समान संख्या शामिल थी। यूक्रेन ने रूस में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए सीधे ड्रोन लॉन्च करने के बजाय एक अलग और बेहद नया तरीका अपनाया। विस्फोटकों से भरे यूक्रेनी ड्रोन्स को लकड़ी के ढांचे के अंदर छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाया गया,इन लकड़ी के ढांचे को ट्रकों पर लादा गया था, जो एयरबेस के पास तक पहुंचाए गए।यूक्रेनी सुरक्षा सूत्र के अनुसार, ये ट्रक टागरेटिड एयरबेस के पास तक पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की गई। इन ड्रोन के अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद लकड़ी के ढांचे की छतें दूर से खोली गईं। इसके बाद ड्रोन ने उड़ान भरी और हमला शुरू कर दिया। ऑपरेशन के सबसे दिलचस्प हिस्से को साझा करते हुए जेलेंस्की ने मीडिया में कहा कि रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन के ऑपरेशन का संचालन करने के लिए ऑफिश एफएसबी के मुख्यालय के ठीक बगल में बनाया गया।क्यों हो रही है पर्ल हार्बर से तुलना?,यूक्रेन ने कहा है कि उसके ड्रोन हमलों में रूस के 41 विमानों को नुकसान पहुंचा है। रूस के न्यूक्लियर कैपेबल टीयू -95, टीयू -22 बमवर्षक और ए-50 विमान इस हमले में तबाह हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि इन विमानों का इस्तेमाल उसकी जमीन पर बमबारी करने के लिए किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने माना है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में मुरमांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवोरियाजान और अमूर एयरबेस को निशाना बनाया गया है।

साथियों बात अगर हम ड्रोन वार भविष्य की हकीकत की करें तो,ड्रोन वॉर-ड्रोन वॉर आने वाले समय में मिलिट्री संघर्ष का आधार होने वाले हैं,ड्रोन तेजी से मुख्यव बल बनने की तरफ बढ़ चुके हैं, यूक्रेन का स्पाइडर वेब हमला इस बात का उदाहरण है कि यूएवी या अनमैन्डक ड्रोन कोई नई चीज नहीं हैं बल्कि आने वाले समय में युद्धों लड़ने के तरीके का आधार हैं, माना जाने लगा है कि सेना, दुश्मन के इलाके में गहराई तक जा सकती है और जेट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है,सबसे बड़ी बात है कि एक भी पायलट का जीवन जरा भी खतरे में नहीं आ सकता है। इसलिए ड्रोन सिस्टेम की तरफ बढ़ना चाहिए,भारत ने अपने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टजर्स और एयरट्रांसपोर्ट में दशकों तक रणनीतिक प्रयास किएहैं,लेकिन स्पाइडर वेब एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करता है,वायु शक्ति का भविष्य मानव रहित, एआई- ऑपरेटेड और लंबी दूरी का होने वाला है, भारत ने उस दिशा में शुरुआती कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक वह स्पी ड नहीं पकड़ सका है जिसकी अपेक्षा की गई थी। यूक्रेन के ऑपरेशन से भारत को स्वदेशी ड्रोन, आर्म्डम यूएवी और ऑटोनमी बेस्डर हथियार सिस्टयम पर कहीं ज्या दा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।

अतः अगर हम उपरोक्त पर्यावरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यूक्रेन ने रूस के घर में 4 हज़ार किऱ्मी अंदर घुसकर ऑपरेशन स्पाइडर वेब (मकड़ी का जाल) को सफ़ल अंजाम देने से पूरा विश्व हैरान-18 महीनों का प्लान 117 ड्रोन,41 बम्बर्स जेट तबाह,वैश्विक स्तरपर अब मिलिट्री संघर्ष का आधार ड्रोन वार होनें की संभावना-यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब से दुनिया सतर्क,यूक्रेन द्वारा रूस में 4 हज़ार किऱ्मी अंदर तस्करी से घुसकर 117 ड्रोन ऑपरेटर सहित एयरबेसो के पास पहुंच जाकर 41 बमबर्स जेट को उड़ाया भारी सुरक्षा चूक -विश्व को हाई अलर्ट पर सुरक्षा संज्ञान लेना ज़रूरी।

(संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

विकास से शुभ संकेत

पहलगाम आतंकी हमले के डेढ़ महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू-कश्मीर यात्रा स्थानीय लोगों के साथ एकजुटता की एक सार्थक पहल ही कही जाएगी। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी रेल परियोजनाओं के उद्घाटन से पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है कि जम्मू-कश्मीर की प्रगति को उसकी तमाम साजिशों के बावजूद धीमा नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके विपरीत पाक पोषित आतंकवादियों द्वारा शांति भंग करने के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद विकास में तेजी लाने के भरसक प्रयास जारी रहेंगे। कश्मीरियों से संवाद कायम करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर पर्यटकों को निशाना बनाने और पर्यटन पर निर्भर लोगों को उनकी आजीविका से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे सीधे-सीधे इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला बताया। निस्संदेह, कश्मीर घाटी को भारत के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ने का सामरिक व प्रतीकात्मक महत्व किसी से छिपा नहीं है। यह सरकार के इस दृष्टिकोण की पुष्टि है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लिंक को जम्मू कश्मीर की नई पहचान और भारत की नई ताकत बताया है। इस प्रकार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पहलगाम के जघन्य हत्याकांड के बाद केंद्र शासित प्रदेश और देश, दोनों ही मजबूत हुए हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की स्पष्ट अभिव्यक्ति न केवल स्थानीय लोगों बल्कि शेष देश से आने वाले पर्यटकों का विश्वास फिर से हासिल करने का सार्थक प्रयास है। इसी तरह के प्रयास राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी किए जा रहे हैं। राज्य के लोगों का मनोबल और पर्यटकों का भरोसा बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले सप्ताह एक सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने पहलगाम की सड़कों पर साइकिल चलाई और जोर देकर कहा कि अब आतंकवाद पर्यटन को नहीं रोक सकता है। वहीं केंद्र सरकार भी इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभा रही है और राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दे रही है। दरअसल, केंद्र सरकार भी लगातार इस दिशा में सक्रिय है कि जम्मू-कश्मीर की कानून व्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। इसमें दो राय नहीं है कि केंद्र व राज्य सरकार के सामने पर्यटकों का भरोसा हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। उन्हें यह भरोसा दिलाना सहज नहीं है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक-ठाक है और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों के प्रति भय और अविश्वास गंभीर स्थिति तक जा पहुंचा था। हालांकि, कश्मीरी लोगों ने पहलगाम घटना के खिलाफ जोरदार विरोध किया था। वे आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगाते हुए बाकायदा सड़कों पर भी उतरे थे। उन्होंने आतंक की घटना का सार्वजनिक तरीके से विरोध करके नई पहल की। निश्चित रूप से सत्ता में बैठे लोगों को उन नफरत फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पुनरुद्धार से होने वाले लाभों को पलीता लगाने पर तुले हैं। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को राष्ट्र को समर्पित, चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हर भारतीय के लिये गर्व का विषय है। बताया जाता है कि यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। साथ ही इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह तूफान, बम हमले और भूकंप के खतरे में भी सुरक्षित रह सकता है। दरअसल, यह पुल चिनाब नदी पर बना और उधमपुर-श्रीनगर के बीच रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है।

राजनीति को नई दिशा देते विपक्षी दलों के नये चेहरें

(लेखक ललित गर्ग)

सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान दुनिया से सहानुभूति बटोरने के लिये जहां विश्व समुदाय में अनेक भ्रम, भ्रांतिया एवं भारत की छवि को छिछालेदार करने में जुटा है, वहीं भारत का डर दिखा-दिखा कर ही पाक अनेक देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है और इन दलों में विपक्षी दलों के सांसद एवं नेताओं ने भारत का पक्ष बिना आग्रह, दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह के दुनिया के सामने रखा, उसकी जितनी सराहना की जाये, कम है। इन विपक्षी नेताओं ने विदेश में भारतीय राष्ट्रवाद को सशक्त एवं प्रभावी तरीकों से व्यक्त किया। देश ने इन नेताओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते और एक लय में आगे बढ़ते देखा, जबकि संसद में वे केवल आपस में लड़ते दिखलाई देते थे। यह सराहनीय पहल भारत के लिये एक बड़ी उपलब्धि बनी है, जो भारत की भविष्य की राजनीति के भी नये संकेत दे रही है। क्योंकि इसने भारत में एक नए एवं सकारात्मक राजनीतिक नेतृत्व को उभरता हुआ दिखाया है। यूं तो सात दलों के सभी सदस्यों ने भरपूर तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का पक्ष रखकर दुनिया को भारत के पक्ष में करने की सार्थक पहल की है, लेकिन कांग्रेस के शशि थरूर एवं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक नये किरदार में नजर आये हैं। थरुर को लेकर कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ से ही विरोध एवं विरोधाभास की स्थितियां बनी हुई।

विदेशों में सटीक एवं प्रभावी भारतीय पक्ष रखने के कारण शशि थरुर जहां असंख्य भारतीयों की वाह-वाही लूट रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी में उनका भारी विरोध हो रहा है। चर्चा एवं विवादों में चल रहे शशि थरूर केरल के तिरुवंतपुरम से चार बार के कांग्रेस के सांसद हैं। वे एक ऐसे कूटनीतिज्ञ राजनेता हैं, जो अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करना जानते हैं। वे एक ऐसे स्वतंत्र सोच एवं साहसी निर्णय लेने वाले नेता भी हैं जो अपनी पार्टी के रुख से अलग भी स्टैंड लेते रहे हैं। लेकिन ताजा सन्दर्भों में वे कांग्रेस के लिए अब असहज सच्चाई बन गए हैं। क्योंकि थरूर ने वह सब कुछ किया है जिसकी पार्टी में इजाजत नहीं है। प्रतिनिधि मण्डल में थरूर के नाम पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। थरूर ने कहा था- मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जब भी राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा।' थरूर ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के सवाल पर कहा- जब आप देश की सेवा कर रहे हों, तब ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद भारत के बॉर्डर के बाहर जाते ही खत्म हो जाते हैं। सीमा पार करते ही हम पहले भारतीय होते हैं। थरूर इन दिनों अमेरिकी सहित कई देशों के दौरे पर हैं, जहां वे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने मल्टी पार्टी डेलीगेशन को सुपर लीड कर रहे हैं। सरकार के समर्थन में बोलने पर कांग्रेस के अनेक नेता थरुर की खिंचाई करने में जुटे हैं। उन्हीं में एक नेता उदित राज ने थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता तक बता दिया है। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान युद्धविराम को लेकर लगातार हमलावर हैं।

4 जून 2025 को राहुल गांधी ने तब हद ही कर दी जब उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं ये सब कहने का अंदाज भी उनका इतना खराब था कि जैसे कोई दुश्मन देश का बंदा बोल रहा हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि, मैं भाजपा और आरएसएस वालों को अच्छे से जान गया हूं, इनको थोड़ा सा दबाओ तो डर कर भाग जाते हैं। राहुल ने आगे कहा, उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदीजी क्या कर रहे हो? नरेंदर, सरेंडर और 'जी हुजूर' करके मोदीजी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस भ्रामक एवं गुमराह करने वाले बयान का थरुर ने जोरदार तरीके से जबाव दिया एवं कांग्रेस पार्टी को ही घेरा। राष्ट्रपति ट्रम्प की भारत-पाक के बीच मध्यस्थता के बयान पर थरूर बोले- मैं यहां किसी विवाद को हवा देने नहीं आया हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति का सम्मान है। हमें नहीं पता उन्होंने पाकिस्तान से क्या कहा, पर हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी।

आग्रह-दुराग्रह से ग्रसित होकर कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को नीचा दिखाने की ही बातें कर रहे हैं, इन कांग्रेसी नेताओं में दायित्व की गरिमा और गंभीरता समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय समस्याएं और विकास के लिए खुले दिमाग से सोच की परम्परा उनमें बन ही नहीं रही है। जब मानसिकता दुराग्रहित है तो दुष्प्रचार ही होता है। कोई आदर्श संदेश राष्ट्र को नहीं दिया जा सकता। राष्ट्र-विरोधी राजनीति एवं सत्ता-लोलुपता की नकारात्मक राजनीति हमें सदैव ही उल्ट धारणा (विपथगामी) की ओर ले जाती है। ऐसी राजनीति राष्ट्र के मुद्दों को विकृत कर उन्हें अतिवादी दुराग्रहों में परिवर्तित कर देती है। राहुल गांधी एवं कांग्रेस ने राष्ट्रीय संकट में भी यही सब करके आम जनता से अधिक दूरियां बना ली है। शशि थरुर ने तो बड़ी लकीरें खींच दी, कांग्रेस कब ऐसी लकीरें खिंचने की पात्रता विकसित करेंगी? हर राजनीतिक दल को कई बार अग्नि स्नान करता पड़ता है, पर आज कांग्रेस तो फ़कीचड़ स्नानफ़ कर रहा है। जहां तक कांग्रेस नेताओं का सवाल है, एक और निहित संदेश सामने आया कि सिर्फ गांधी परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकता जबकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी में अभी भी प्रतिभाओं का खजाना है, उसके पास अनुभवी नेता हैं, जो जटिल मुद्दों को समझने और नेतृत्व देने में सक्षम हैं।

बड़ी लकीरें तो प्रतिनिधिमण्डल में गये अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी खींची है। जिनमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विश्व की राजधानियों में भारत की स्थिति और मौजूद विकास को भी रेखांकित किया है। ओवैसी- जो भारत के अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं- उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी भाषा में आड़े हाथों लिया।

(चिंतन-मनन)

मृत्यु के उपरांत शरीर नष्ट हो जाता है

अष्टावप्र गीता में आचार्य अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य शरीर मात्र शरीर नहीं है। वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर की पोषक है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है, शरीर विकृत होने लगता है। बुद्धि, कर्म, भोग, अहंकार, लोभ, मोह शरीर और मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति हुआ करती है कि मैं एक शरीर हूं, आत्मा नहीं। यही तो अज्ञान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच तत्वों से मिलकर शरीर बनता है, जो भौतिक, अनित्य और नष्ट होने वाला है। मृत्यु के उपरांत शरीर नष्ट हो जाता है, पर हम शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी अगली यात्र पर निकल जाते हैं। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। यह शरीर हमारा वस्त्र मात्र है, जो भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है। हम सब घर नहीं, बल्कि इसमें रहने वाले मालिक हैं। हम बार-बार यह कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, जो चैतन्य है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, वह ब्राण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। वह तो चैतन्य-शक्ति मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है और न आश्रम वाली है। आत्मा की न कोई जाति होती है और न ही कोई धर्म होता है। ये चार आश्रम-ब्राचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वाली भी नहीं है। आत्मा न कर्ता है और न भोक्ति है और न ही भोग्य विषय है। इन तीनों से परे असंग, निराकार और साक्षी मात्र है। 1कुछ लोग कहते हैं कि यह घोर कलयुग है, यह पंचम काल है। इसमें तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस संदर्भ में आचार्य अष्टावप्र कहते हैं कि तुम अपने को चैतन्य में स्थिर कर लो तो अभी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, उसी तरह क्या आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार गायब नहीं हो सकता। अज्ञान के मिटते ही जीव की सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। आत्मा चैतन्य है, मुक्ति है, सर्वत्र व्यापक है, वह किसी बंधन में बंधी नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, वह निराकार है। उसी निराकार का रूप सृष्टि है। आकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। जैसे सोने से विभिन्न आभूषण बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व सोना वही रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही सनातन है।

विचार मंथन

उधार के चंदन से कैसे ठीक होगी अर्थव्यवस्था

(लेखक - सनत जैन)

भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने विगत दिवस बैंक की ब्याज दरों में डबल कटौती कर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। रिजर्व बैंक के इस निर्णय के बाद शेयर बाजार आसमान में झूमने लगा। बैंक निफ़्टी, रियल्टी, ऑटो सेक्टर रॉकेट की तरह आकाश में कुलाचें भरने लगे हैं। रिजर्व बैंक की इस घोषणा के बाद सेंसेक्स 747 अंकों की वृद्धि के साथ हवा हवाई हो गया। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जीडीपी को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास शुरु कर दिये हैं। शेयर बाजार का भी जीडीपी में बहुत योगदान होता है। बैंकों में नगदी की कमी बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को ढाई लाख करोड रुपए की संजीवनी दे दी है। यह संजीवनी सीएसआर में एक फ़ीसदी की कटौती कर के दी है। पहले रेपो रेट की दर चार फ़ीसदी थी। रिजर्व बैंक ने इसे घटाकर तीन फ़ीसदी कर दिया है। जिसके कारण बैंकों के पास लगभग ढाई लाख करोड रुपए अतिरिक्त पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ने बैंक रेट को 5.75 फ़ीसदी कर दिया है। इसका लाभ यह होगा कि लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। ईएमआई कम होगी। ब्याज कम होने के कारण बैंक अब एफडी सेविंग के ब्याज दरों में कमी करेंगे। इसका तात्कालिक लाभ अर्थव्यवस्था को संभालने और जीडीपी बढ़ाने में कुछ समय के लिये जरूर मिल सकता है। उसका दीर्घकालीन नुकसान होना तय है। बैंकों में यदि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में कम राशि जमा होगी। ऐसी स्थिति में बैंकों को दौहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक के उपरोक्त सभी प्रयासों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई दीर्घकालीन लाभ मिलने जा रहा हो ऐसा कहीं से दिखता नहीं है। सीएसआर में कटौती करके रिजर्व बैंक ने बैंकों की तरलता को बढ़ा दिया है। कुछ समय के लिए इसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। लेकिन दीर्घकालीन नुकसान होना तय है। बैंकों ने ब्याज दरों में जो कटौती की है। उसके कारण सस्ते लोन मिलने की आशा बढ़ी है। यह लोन सही हाथों तक पहुंचेगा और बैंकों को वापस लौटेगा, इसमें संदेह है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से बैंकों से जो ऋण दिलवाया जा रहा है। उसका एनपीए साल दर बढ़ता ही चला जा रहा है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाकर बैंकों में जिन लोगों का धन जमा है, उनके जोखिम को बढ़ा दिया है। किसी भी बैंक के पास 100 रुपये जमा होंगे, तो उसे मात्र 3 रुपये ही रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखने होंगे। बाकी 97 रुपए वह लोन बांट सकेगा। यदि बैंक ऋण समय पर वापस नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जमाकर्ताओं का जोखिम बहुत बढ़ जाएगा। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के भंडार को 15 फ़ीसदी तक सीमित रखने का निर्णय लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आयात जरूरतों को देखते हुए यह मुद्रा भंडार आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अर्थव्यवस्था को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल प्रभाव को देखते हुए जिस तरह का निर्णय ले रहा है। उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है उधार के चंदन से अपने ललाट पर टीका लगाकर रिजर्व बैंक दूसरों को दिखा तो रहा है, लेकिन ना तो टीका हमारा है, ना चंदन हमारा है। आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है।

जमाकर्ताओं का जो धन बैंकों के पास जमा है। बैंक य दि दिवा लिया होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीमा से केवल 5 लाख रुपये वापस मिलेगा। इससे जमाकर्ता बैंकों से अपना धन निकालकर रियल स्टेट अथवा सोना-चांदी में निवेश कर रहे हैं। जिसके कारण बैंकों का जो खिम भी बढ़ रहा है।

यदि समय रहते गंभीरता से अर्थव्यवस्था को लेकर सही निर्णय नहीं किए गए। इसके दुष्परिणाम आने वाले कई दशकों तक हमें देखने पड़ेंगे। सरकार और रिजर्व बैंक को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए दीर्घकालीन निर्णय लेने होंगे।

रूस के केंद्रीय बैंक ने की नीतिगत ब्याज दर में 1 फीसदी कटौती

नई दिल्ली।

रूस के केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में 1 फीसदी की कटौती कर दी है।` जिससे रूस की नई बेंचमार्क पॉलिसी रेट 21 से घटकर 20 फीसदी हो गई है। यह सितंबर 2022 के बाद पहली बार है जब रूस ने ब्याज दरों में कटौती की है। फरवरी 2022 से ही यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे संतुलित विकास की ओर लौट रही है। रूस में अप्रैल 2025 में मुद्रास्फीति दर 6.2 फीसदी दर्ज की गई, जबकि पहली तिमाही में यह औसतन 8.2 फीसदी थी। रूस की मुद्रा रूबल साल 2025 में डॉलर के मुकाबले दुनिया में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाली करंसी बन गई है। रूबल का बढना और महंगाई का कम होना बताता है कि रूस द्वारा अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति अब असर दिखा रही है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि नीति अब भी सख्त रहेगी, जब तक कि महंगाई को 4 फीसदी के लक्ष्य तक नहीं लाया जाता। बैंक का कहना है कि घरेलू मांग अब भी आपूर्ति के मुकाबले ज्यादा है।

मुकेश अंबानी ने आईसीटी को 151 करोड़ अनुदान देने की घोषणा की

मुकेश अंबानी ने 1970 के दशक में यहीं से की थी स्नातक की पढ़ाई

मुंबई।

देश के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) को 151 करोड़ रुपये का बड़ा दान देने की घोषणा की। ये दान उन्होंने अपने पुराने शिक्षक प्रोफेसर एमएम शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया। यहीं से उन्होंने 1970 के दशक में स्नातक की पढ़ाई की थी। हाल ही में आईसीटी के वरिष्ठ और सम्मानित प्रोफेसर एमएम शर्मा की जीवनी डिवाइन साइंटिस्ट के विमोचन समारोह में मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रोफेसर शर्मा और जेबी जोशी मेरे प्रोफेसर थे। अन्य संस्कृतियों में गुरु केवल शिक्षक होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं...मुकेश अंबानी ने कहा, 70 के दशक के मध्य में जब मैं एक छात्र के रूप में यहां आया था, तब यह इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं था, यह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी था। मैंने जानबूझकर आईआईटी बॉम्बे की जगह यूडीसीटी को चुना था। आज भी मुझे प्रोफेसर शर्मा का पहला व्याख्यान याद है और उन्हें सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि मैंने सही चुनाव किया है।

एसबीआई एमएफ, गोल्डमैन सैक्स, अन्य ने बजाज फिनसर्व में खरीदी हिस्सेदारी

नई दिल्ली।

एसबीआई एमएफ, मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स सहित अन्य ने बजाज फिनसर्व में प्रवर्तक संस्थाओं से कुल 5,506 करोड़ रुपये में 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी। एनएसई पर थोक सौदों के आंकड़ों के अनुसार जेपी मॉर्गन इंडिया, सिटीग्रुप ग्लोबल, सोसाइटी जनरल, एसबीआई लाइफ, बोफा सिक्योरिटीज और बार्कलेज मर्चेंट बैंक (सिंगापुर) भी खरीदारों में शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार इन संस्थाओं ने बजाज फिनसर्व में 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,925.20 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर खरीदी। इस तरह संयुक्त लेनदेन मूल्य 5,506.07 करोड़ रुपये हो गया। इस बीच बजाज फिनसर्व की प्रवर्तक इकाई बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट और जमनालाल संस ने समान कीमत पर समान संख्या में शेयर बेचे। हिस्सेदारी बिक्री के बाद बजाज फिनसर्व में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 60.64 प्रतिशत से घटकर 58.84 प्रतिशत रह गई।

सरकार बनाएगी विदेशी दिग्गज फर्मों को टक्कर देने वाली कंपनी

भारत की कंपनी बनने से विदेशी परामर्श कंपनियों पर निर्भरता हो जाएगी कम

नई दिल्ली।

केंद सरकार भी दु निया की चार दिग्गज परामर्श एवं ऑडिट कंपनियों को टक्कर देने वाली कंपनी बनाने की योजना बना रहा है। कंपनी मामलों के मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति ऐसी देसी कंपनी बनाने के लिए जरूरी कदमों पर विचार करेगी।

यह समिति जरूरत पड़ने पर नीतिगत उपाय भी सुझाएगी। इस सिलसिले में हाल ही में पहली बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में हुई थी। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराज, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव और गौर मुखर्जी समेत शीर्ष सरकारी अधिकारी शामिल हुए थे।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने इन शीर्ष अधिकारियों के समक्ष वैश्विक स्तर की एक ऐसी भारतीय कंपनी तैयार करने का खाका पेश किया। सूत्रों ने कहा कि इस बैठक से पहले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने भी इस विषय पर अपनी सलाह कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को दी थी। चार बड़ी कंपनियों डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों से काफी काम मिलता है। अब सरकार चाहती है कि ऐसी कंपनियों पर निर्भरता कम कर देश में ही एक कंपनी तैयार की जाए, जो ये काम कर सके।

पीएनबी ने घटाई होम और ऑटो लोन की ईएमआई

ब्याज दरों में कटौती 9 जून से प्रभाव में आएगी

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रेपो रेट में कटौती के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने होम और ऑटो लोन की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। पीएनबी ने बताया कि बैंक ने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में 0.50 फीसदी की कमी की है, जो 9 जून 2025 से प्रभाव में आएगी। इसके तहत अब पीएनबी का होम लोन 7.45 फीसदी और ऑटो लोन 7.80 फीसदी सालाना की दर से शुरू होगा। बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा` कि हमारे ग्राहकों के लिए खुशखबरी, आपकी ईएमआई को अब और भी सस्ता बना दिया गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक में रेपो दर को 0.50 घटाकर 5.50 फीसदी कर दिया गया, जो कि फरवरी से अब तक कुल एक फीसदी की कटौती है। यह दर पिछले तीन वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उम्मीद जताई कि ब्याज दर में हुई कटौती से देश की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि, इस निर्णय का असर वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।

पाकिस्तान अंदर से खोखला, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से खुलासा

लगभग 44.7 फीसदी पाकिस्तानी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है

नई दिल्ली। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी` बिगड़ गई है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक की ह्मली ह्मलिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 44.7 फीसदी पाकिस्तानी आबादी अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है, जो कि चिंताजनक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति सिर्फ शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आमिस मुनीर की असफलता का ही परिणाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की स्वाभाविकता को भी दर्शाता है। पाकिस्तान ने आतंकी साजिशों की बढ़ती चपेट में आर्थिक सहायता और अन्य आंकड़ों पर निर्भर होने की स्थिति में विकास के मामले में पीछे हो जाना है। अंतरराष्ट्रीय कर्ज और राहत पैकेजों पर निर्भर रहने वाले पाकिस्े तान की आज भी प्राथमिकता देश का विकास नहीं बल्कि आतंकवाद को पालने-पोसने की है। चाहे आईएमएफ हो या फिर चीन जैसे मित्र देश, हर जगह से पाकिस्े तान को भर-भरकर अरबों डॉलर का कर्ज़ मिल रहा है। इसके बावजूद वहां आवाम के जीवन स्तर में कोई ठोस सुधार नहीं आ पाया है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी अब रोजाना 1200 रुपये से भी कम पर गुजारा कर रही है, जो इस बात को साफ करता है कि सत्ताधारी वर्ग की योजनाएं जमीनी सच्चाई से कोसों दूर हैं। विकास के बजाय पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता आज भी उसकी सेना और आतंकवाद को समर्थन देना है। ह्मलिया वर्षों में पाकिस्तान ने सेना के बजट में लगातार इजाफा किया है। इतना ही नहीं वहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस वर्ष भी पाकिस्तान की सेना को बजट में भर-भरकर पैसा दिया गया है, जबकि देश में 39.8 मिलियन लोग चरम गरीबी की मार झेल रहे हैं।

सेंसेक्स और निफ्टी में एक फीसदी की तेजी रही

सेंसेक्स 746.95 अंक चढ़कर 82,188.99 पर बंद

निफ्टी 817.55 अंक चढ़कर 56,578.40 पर बंद

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट में 50 बे सिस अंकों और सीआरआर में 100 बे सिस अंकों की कटौती की वजह से लगातार दो सप्ताह से चली आ रही` गिरावट के` सिले सिले को तोड़ते हुए 6 जून को समाप्त सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी में एक फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए। बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में एक फीसदी की तेजी देखी गई। शेयर बाजार सप्ताह में पहले और दूसरे` दिन` गिरावट ले किन बाकी तीन` दिन बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। शेयर बाजार में सप्ताह के पांच` दिन कारोबार इस प्रकार रह्मा- एशियाई बाजारों से मिलेजुले रूखे के बीच भारतीय शेयर बाजार जून महीने के पहले कारोबारी` दिन सोमवार को बड़ी गिरावट लेकर लाल निशान में खुले। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक गिरकर 81,214 पर खुला और 77.26 अंक गिरकर 81,373.75 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी गिरावट के साथ 24,669.70 अंक पर खुला और 34.10 अंक गिरकर 24,716.60 पर बंद हुआ। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 194.65 अंक गिरकर 81,179.10 पर खुला और 636.24 अंक की गिरावट के साथ 80,737.51 पर बंद हुआ। निफ्टी 62.35 अंक गिरकर 24,654.25 पर खुला और 174.10 अंक गिरकर 24,542.50 पर बंद हुआ। दो दिन की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 192.73 अंक के साथ 80,930.24 पर खुला

और 260.74 अंक या 0.32 प्रतिशत चढ़कर 80,998.25 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 174.10 अंक गिरकर 24,542.50 पर खुला और 77.70 अंक बढ़कर 24,620.20 अंक पर बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 197.83 अंक चढ़कर 81,196.08 पर खुला और 443.79 अंक चढ़कर 81,442.04 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 71 अंक चढ़कर 24,691.20 पर खुला और 130.70 अंक बढ़कर 24,750.90 पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर एमपीसी के फैसलों के एलान के बाद घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी लौटी। सेंसेक्स 755.89 (0.92 फीसदी) अंकों की बढ़त के साथ 82,197.93 पर खुला और 746.95 अंक या 0.92 प्रतिशत चढ़कर 82,188.99 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी मजबूत खरीदारी दिखी और यह 849.55 (1.52 फीसदी) अंक मजबूत होकर 56,610.40 के स्तर पर खुला और 817.55 (1.47 फीसदी) अंक चढ़कर 56,578.40 के स्तर पर बंद हुआ।

चीन में इलेक्ट्रिक सेडान मैक्सट्रो एस 800 लॉन्च

नई दिल्ली।

चाइनीज कंपनी हुवावे ने अपने नए लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान मैक्सट्रो एस 800 को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपये यानी एक मिलियन युआन से अधिक है। यह कार शेन्जेन में पिछले सप्ताह पेश की गई और इसे मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस, रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे और बेंटले जैसी अल्ट्रा-लक्जरी कारों के मुकाबले उतारा गया है। मैक्सट्रो एस 800 का डिजाइन मर्सिडीज-मेबैक की लक्जरी वाइब देता है, जिसमें फ्रंट पर स्लीक एलईडी हेडलैम्प और सिल्वर जाली लगी है। इसके बड़े मल्टी-स्पोक पहिये, क्रोम ट्रिम्स, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल और कूपरूफलाइन इसे आकर्षक बनाते हैं। कार के विंडशील्ड पर लिडार पैनल भी मौजूद है, जो एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (अडास) का हिस्सा है। इंटीरियर की बात करें तो केबिन में क्रिस्टल शिमर सीलिंग है, जिसे रोल्स-रॉयस ने भी इस्तेमाल किया है, जिससे छत तारों भरे आसमान जैसी लगती है। तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड और 32 से अधिक अडास सेंसर इस कार को तकनीकी रूप से अत्याधुनिक बनाते हैं। हुवावे ने पहले भी सेरेस ग्रुप के साथ ऑटोमोटिव सेक्टर में कदम रखा है और अब मैक्ट्रो एस 800 के साथ लग्जरी कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।

यह मॉडल 838 बीएचपी की पीक पावर देने में सक्षम है और कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ हुवावे इलेक्ट्रिक लग्जरी कारों के क्षेत्र में मर्सिडीज, रोल्स-रॉयस और बेंटले जैसे ब्रांडों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। बता दें कि चाइनीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां अब तेजी से इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बाजार में कदम रख रही हैं और इस रेस में हुवावे ने भी अपनी एंट्री कर ली है।

पामतेल के शुल्क में कटौती से कीमत स्थिर करने में मदद मिलेगी:विशेषज्ञ

नई दिल्ली।

पाम, सोया और सूरजमुखी सहित खाने के तेलों पर आयात शुल्क में कटौती करने से एफएमसीजी कंपनियों को अपने मार्जिन में सुधार करने और लागत को स्थिर करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। उन्होंने कहा कि दैनें दिन की जरूरत का सामान बनाने वाली कंपनियां खाद्य पदार्थों में पाम तेल का उपयोग करती हैं।` जिससे न केवल खाद्य कंपनियों को फायदा होगा, जिनके लिए पामतेल उनके कच्चे माल की लागत का लगभग 25-30 प्रतिशत है, बल्कि साबुन निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद पीएफएडी (पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट) की कीमतें भी कम होंगी। सरकार ने पिछले सप्ताह कच्चे खाद्य तेलों पर मूल आयात कर में 10 प्रतिशत की कमी की थी। शुल्क में कटौती 31 मई, 2025 से प्रभावी है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल), जो सिंथॉल और गोदरेज नंबर वन जैसे साबुन ब्रांडों का मालिक है, ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया। वैश्विक पाम ऑयल की कीमतों में नरमी के शुरुआती संकेतों के साथ-साथ यह कदम लागत को स्थिर करने में मदद करेगा। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत शुल्क कटौती उपभोक्ता मासिक मुद्रास्फीति को कम करेगी और खाद्य कंपनियों की लागत को कम करेगी।

भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर रहा स्टील सेक्टर

वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक स्टील उत्पादन स्थिर रहा

नई दिल्ली।

टाटा स्टील के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने शेयरधारकों को एक पत्र लिखकर बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने जनसंख्या संरचना, ढांचागत सुधार, कम महंगाई और सरकारी छूटों के चलते देश की आर्थिक स्थिति की प्रशंसा की। चंद्रशेखरन ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक स्टील उत्पादन स्थिर रहा, जबकि भारत में स्टील का उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई है। टाटा स्टील ने भी देश में अपनी प्रबल प्रतिष्ठा बनाई है। कंपनी ने देशभर में योगदान देते हुए अपनी स्थिरता और विश्वसनीयता साबित की है। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील ने सबसे ज्यादा कच्चा इस्पात उत्पादन किया और भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन किया है। कंपनी ने ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस शुरू किया है, जिससे उनके पूर्वानुमान के अनुसार स्टील उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ने भी अच्छे प्रदर्शन किया है। टाटा स्टील ने भारत में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने देशभर में अपनी फैक्ट्रियों को लगभग पूरी क्षमता पर चलाया और अब तक का सबसे ज्यादा कच्चा इस्पात उत्पादन किया, जो 21.7 मिलियन टन रहा। इस दौरान 20.9 मिलियन टन स्टील की डिलीवरी भी की गई। कंपनी ने ओडिशा के कलिंगनगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस शुरू किया है, जो 27,000 करोड़ की फेज-2 विस्तार योजना का हिस्सा है। इसके अलावा, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 1,000 करोड़ का ऐ बिटा दर्ज किया और सकारात्मक फ्री कैश फ्लो भी हासिल किया।

इलेक्ट्रिक एसयूवी वीएफ 6 और 7 की टेस्टिंग शुरू

नई दिल्ली।

इलेक्ट्रिक एसयूवी निर्माता कंपनी विनफास्ट ने अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी वीएफ6-7 की भारत में टेस्टिंग शुरू कर दी है। विनफास्ट की मुंबई समेत कई बड़े शहरों में टेस्टिंग जारी है, जिसमें कंपनी अपने वीएफ6 और वीएफ7 मॉडल की सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क के साथ अनुकूलता और रियल-रंग रेंज का आकलन कर रही है। इसका मकसद यह समझना है कि ये वाहन भारत के विभिन्न इलाकों में उपलब्ध चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कितना अच्छा तालमेल बिठा पाते हैं। विनफास्ट की योजना है कि वे इस साल के फेस्टिव सीजन में भारत में अपने इलेक्ट्रिक एसयूवीएस को लॉन्च करें। कंपनी ने भारत में अपनी सहायक कंपनी वी-ग्रीन चार्जिंग समाधान लाने की भी घोषणा की है, जो 60केडब्ल्यू से लेकर 300केडब्ल्यू तक की क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, विनफास्ट ने टाटा पावर जैसे स्थानीय चार्जिंग पार्टनर के साथ भी सहयोग किया है, ताकि चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत बनाया जा सके और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिले। विनफास्ट की एसयूवीएस भारत के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होंगी और कंपनी 5-स्टार भारत एनकैप सुरक्षा रेटिंग के लिए भी काम कर रही है। वीएफ6 और वीएफ7 दोनों ही 5-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवीएस हैं, जिनमें 75.3 केडब्ल्यूएच की बैटरी लगी है। वीएफ7 में सिंगल मोटर वाला फ्रंट-व्हील ड्राइव 201 बीएचपी की पावर और 310 एनएम का टॉर्क देता है, जबकि डुअल मोटर वाला ऑल-व्हील ड्राइव वैरिएंट 348 बीएचपी पावर और 500 एनएम टॉर्क के साथ आता है। दोनों मॉडलों की रेंज लगभग 431 से 450 किलोमीटर के बीच है। कारें 35 मिनट में डीसी फास्ट चार्जर से 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती हैं। विनफास्ट ने भारतीय बाजार के लिए विशेष फीचर्स जैसे लेवल 2 अडास, एडजस्टेबल सीटें, और बड़े इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिए हैं।

विंडसर ईवी ने 6,304 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की

नई दिल्ली।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने मई 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6,304 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। कंपनी की यह बिक्री पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा रही। विंडसर ईवी को लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। यह बढ़ोतरी एमजी की मजबूत ईवी पोर्टफोलियो, खासकर विंडसर ईवी और उसके प्रो वेरिएंट्स की बदौलत संभव हो पाई है। हाल ही में लॉन्च हुई विंडसर ईवी प्रो सीरीज ने इस रफ्तार को और तेज किया है। कंपनी ने एसेंस प्रो और एक्सक्लूसिव प्रो जैसे वेरिएंट्स उतारे हैं, जो 52.9 केडब्ल्यूएच की बैटरी से लैस हैं और एक बार चार्ज करने पर 449 किमी तक की प्रमाणित रेंज देती हैं। इनमें लेवल 2 अडास, व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) और व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे ये कारें सुरक्षा और तकनीक के मामले में काफी आगे हैं। एमजी ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैट्री-एस-ए-सर्विस (बीएएएस) मॉडल भी पेश किया है, जिसमें ग्राहक बैटरी खरीदने की बजाय किराये पर ले सकते हैं। इससे वाहन की शुरुआती कीमत घटती है और ज्यादा लोगों तक ईवी पहुंच बनती है। कंपनी आने वाले महीनों में तीन नए इलेक्ट्रिक व्हीकल—साइबस्टेर, एम9 एमपीवी और माजेस्टेर एसयूवी लॉन्च करने की योजना में है। एमजी की लगातार बढ़ती बिक्री दर्शाती है कि अब ग्राहक सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि तकनीक, रेंज और वैल्यू को प्राथमिकता दे रहे हैं।

टू-व्हीलर बिक्री में हीरो ने होंडा को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली।

दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो ने होंडा को मासिक और वार्षिक दोनों आधार पर पीछे छोड़ दिया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई 2025 में टू-व्हीलर सेगमेंट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मई में हीरो ने 4,88,997 वाहन बेचे, जो अप्रैल 2025 में उसके 2,88,254 से लगभग 70प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्शाता है। वहीं, होंडा की बिक्री मई में 4,17,256 रही, जो अप्रैल के 4,22,931 की तुलना में करीब 1.34प्रतिशत की गिरावट है। सालाना आधार पर होंडा को मई 2024 की तुलना में 7.4प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ा। टॉप टू-व्हीलर ब्रांडों की बात करें तो टीवीएस ने मई 2025 में 3,09,287 बाइकें बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 14प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जबकि बजाज की बिक्री में मामूली वृद्धि के साथ 1.63प्रतिशत की वार्षिक ग्रोथ दर्ज की गई। सुजुकी ने भी 17प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी के साथ 1,07,780 इकाइयां बेचीं। वहीं, रॉयल एनफील्ड ने सबसे बड़ी सालाना ग्रोथ दिखाई, जिसकी बिक्री मई 2025 में 75,820 रही, जो पिछले साल की 63,531 से 19.34प्रतिशत अधिक है। मासिक आधार पर देखें तो बजाज और सुजुकी ने क्रमशः 1.48प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की, जबकि टीवीएस और रॉयल एनफील्ड की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय टू-व्हीलर बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है, जहां हीरो ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए होंडा को चुनौती दी है।

भारत में कोविड मामलों में फिर उछाल, एक्टिव केस 5 हजार के पार, केरल सबसे प्रभावित राज्य

नई दिल्ली।

भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेज़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या बढ़कर 5,364 हो गई है, जो पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 अधिक है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में चार नई मौतों की भी पुष्टि की गई है। केरल एक बार फिर सबसे अधिक प्रभावित राज्य बनकर सामने आया है, जहां वर्तमान में 1,679 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596 और दिल्ली में 592 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में दो मौतें दर्ज की गईं, जबकि कर्नाटक और पंजाब में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु कोविड के चलते हुई है। कोविड मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकतर मामलों में लक्षण हल्के होते हैं और मरीजों को घर पर ही इलाज दिया जा रहा है। हालांकि संभावित संक्रमण की लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में 2 और 3 जून को तकनीकी समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी, जिनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) और दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

इन बैठकों में मौजूदा स्थिति की गंभीरता और तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।

मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि देशभर में आईएलआई (इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी) और

एसएआरआई (गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण) के मामलों पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस साल जनवरी से अब तक देश में कुल 4,724 कोविड मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 55 मौतें दर्ज की गई हैं। 22 मई को देश में केवल 257 सक्रिय मामले थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 5,000 से अधिक हो चुकी है। मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है।

इंडियन नेवी में शामिल होगा अर्नाला, बेहद खतरनाक है एंटी-सबमरीन वारफेयर

नई दिल्ली।

भारतीय नौसेना 18 जून को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में पहले 'एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट'अर्नाला अपने बेड़े में शामिल करेगी। अर्नाला उन 16 छोटे वॉरशिप्स में से एक है, जिन्हें नेवी में कमीशन किया जाना है। इन वॉरशिप्स को समुद्र तटों पर एंटी-सबमरीन लड़ाइयों और छोटे स्तर के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इन सभी को 12,622 करोड़ रुपए की लागत से भारत में ही तैयार किया गया है। आईएनएस अर्नाला की तैनाती से भारत की तटीय सुरक्षा मजबूत होगी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। एएसडब्लू-यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट कई खासियतों से लैस है। यह तट से 100 से 150 नॉटिकल मील दूरी पर दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकती है।समुद्र के अंदर यह 30-40 मीटर की गहराई वाले इलाकों में अभियान चला सकती है। दुश्मन की सबमरीन का खतरा भांपकर यह उसे खत्म करने में सक्षम है।अर्नाला में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, लाइट वेट टॉरपीडो, 30 एमएम नेवल गन, एएसडब्लू कॉम्बेट सूट, हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वैरियेबल डेप्थ सोनार से लैस है। इसकी रफ्तार 25 नॉटिकल मील प्रति घंटे होगी। एक बार में यह 3300 किलोमीटर तक जा सकता है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहाकि 80 फीसदी स वदेशी तकनीक से निर्मित यह पोत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एलएंडटी, महिंद्रा डिफेंस और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) समेत प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियों की उन्नत प्रणालियों से युक्त है। उन्होंने कहाकि अर्नाला पोत के नौसेना बेड़े में शामिल होने से यह भारत की नौसैनिक क्षमताओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि इससे तटीय सुरक्षा मजबूत होगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में यह आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ बनाएगा।

चीन की साख पर लगा बट्टा- हथियारों के कॉम्बैट डेब्यू में भारत हुआ पास

नई दिल्ली।

भारत लंबे समय से दो मोर्चों पर युद्ध की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहा था। नई तकनीक के हथियार खरीदे गए, लेकिन अब तक वे सिर्फ फायरिंग रेंज में ही अभ्यास कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सभी हथियारों को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया, जिससे उनका कॉम्बैट डेब्यू हो गया। मजेदार बात तो यह है कि लड़ाई तो भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे। एक्सपोज चीन हो गया। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की है। अब तक इसे केवल ट्रायल के दौरान ही फायर किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का टेस्ट भी हुआ। एयर बेस और रनवे पर बने बड़े गड्ढे ने इसकी क्षमता की गवाही दे दी। भारत ने अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। ऑपरेशन सिंदूर में इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ। इस सिस्टम की खासियत है कि यह 600 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी दुश्मन के हवाई हमले को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। पाकिस्तान के हमलों को भारतीय जमीन पर मलबे के तौर पर गिराने का श्रेय मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल ÷अभ्रा÷ और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। लद्दाख से लेकर राजस्थान तक कुल 6 आकाश तीर नोड या कमांड पोस्ट एक्टिव थे। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सैकड़ों ड्रोन को हिट करने में आकाश तीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।भारत को पता था कि पाकिस्तान पलटवार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत वाले दिन ही चीन के हथियारों की साख पर सवाल उठ गए थे, जब पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर और मुरीदके में अटैक को पकड़ नहीं सका।

अगले हफ्ते फ्रांस के दौरे पर जा रहे जयशंकर

नई दिल्ली।

अगले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में फ्रांस, भारत के साथ खड़ा होकर आतंकवाद के खिलाफ अभियान में मदद कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों ने आंतकियों के ठिकानों को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत, पश्चिमी देशों में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है।

साथ ही, पाकिस्तान की ओर से यूएनएससी में उठाने वाले मुद्दों को रोकने के लिए फ्रांस पर भी निर्भर है। वहीं फ्रांस दशकों से आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दे रहा है। अब दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग में भी सहयोग बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा पर जा रहे है। फ्रांस भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करता है। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर, फ्रांस के अधिकारियों से मिलने वाले है।

पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही भारत में फ्रांस के दूतावास ने पोस्ट लिखकर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग उठाई थी। फ्रांस ने कहा था, आज से फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाली है।

इसका मतलब है कि फ्रांस अब वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत का नेतृत्व करेगा। आज की दुनिया को देखते हुए यूएनएससी में बदलाव जरूरी है। भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए।

अपने दौरे के दौरान जयशंकर मार्सिले में भारत-फ्रांस ट्रैक 1.5 संवाद को भी संबोधित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर किया जा रहा है।

पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देगी योगी सरकार, आदेश जारी

लखनऊ।

उप्र पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर के रूप में चार वर्ष की सेवा देने वाले वालों को यह लाभ दिया जाएगा।

इस निर्णय का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सार्थक अवसर देना है। आरक्षण सभी श्रेणियों (सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी) पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी श्रेणी से संबंधित है तो आरक्षण एससी के भीतर लागू होगा। वहीं, अगर ओबीसी है तो ओबीसी के भीतर होगा। आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसी श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीर उन्हें ही माना जाएगा जो चार साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे। इनकी यूपी का मूल

निवासी होने की शर्त रहेगी। बात दें कि योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब गृह विभाग ने 20 प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है। इस प्रणाली के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा। कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की पहल की हैं। हरियाणा व ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10त आरक्षण की पेशकश की है।

बिक्स में शामिल कई मुस्लिम देशों ने दिया पाकिस्तान को झटका

नई दिल्ली।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा जारी है। इसी कड़ी में ब्रासीलिया में आयोजित बिक्स संसदीय मंच ने हमले की कड़ी निंदा कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि इसमें चीन के अलावा कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। मंच में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। बिड़ला ने कहा कि आतंकवाद आज वैश्विक

संकट बन चुका है, जिसका सामना अंतरराष्ट्रीय सहयोग से हो सकता है। उन्होंने चार प्रमुख कदमों की वकालत की। उसमें आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद बंद हो, इंटेलिजेंस साझा करने की प्रक्रिया तेज हो, तकनीक के दुरुपयोग को रोके और जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला की इन बातों को बैठक में मौजूद सभी देशों ने एकमत से स्वीकार कर अंतिम घोषणापत्र में शामिल किया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, संयुक्त घोषणापत्र में भारत के पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई और सभी बिक्स देशों के संसदों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करने की सहमति दी। बैठक में आतंकवाद के अलावा एआई, वैश्विक व्यापार, अंतर-संसदीय सहयोग, और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

देशभर की मस्जिदों में लाखों लोगों ने मांगी अमन-चैन की दुआ, दिग्गजों ने दी मुबारकबाद

नई दिल्ली।

बकरीद के मौके पर देशभर की मस्जिदों में लाखों लोगों ने अमन और शांति की दुआ की। ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया, जहां लाखों लोग एकजुट होकर मुल्क की सलामती और अमन-चैन की दुआएं मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, बिहार से दिल्ली तक, हर जगह लोग एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खड़गे ने सभी मुस्लिम भाईयों का मुबारकबाद दी है।

राजधानी दिल्ली में भी बकरीद पर मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की जा रही है। डीसीपी विचित्र वीर ने बताया, कई दिनों से थाना और सब-डिवीजन स्तर पर तैयारियां की गई थीं। मस्जिद कमेटियों और अमन कमेटियों से संपर्क कर लोगों को शांतिपूर्ण नमाज और कुर्बानी के लिए जागरूक किया गया। पश्चिमी जिले में 29 मस्जिदें हैं, जिनमें कुछ बड़ी मस्जिदों में हजारों लोग नमाज के लिए जुटे। सभी जगह विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ईद-उल-अजहा की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। शहर की ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला अधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) सहित भारी पुलिस बल ईदगाह के बाहर मौजूद रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अलीगढ़ और वाराणसी में भी बकरीद का उत्साह चरम पर रहा। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई और लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। नमाजी आलम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, हमने मुल्क की सलामती और भाईचारे के लिए नमाज पढ़ी। आज का दिन खुशी का दिन है। हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रेम और एकता के साथ रहें।

ईद-उल-अजहा पर खुर्जा की ईदगाह में भी सैकड़ों की संख्या में नमाजी एकत्र हुए और नमाज अदा की। इस दौरान अतिरिक्त जिला अधिकारी (एडीएम), पुलिस अधीक्षक (देहात), उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और क्षेत्राधिकारी (सीओ) सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुलंदशहर पुलिस अलर्ट मोड में है और हर गतिविधियों की ड्रोन से निगरानी कर रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और अमन की दुआ मांगी।

5वीं जेन का फाइटर ले रहा पाकिस्तान, पॉयलेटों ने चीन डाला डेरा

नई दिल्ली।

पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट इस वक्त चीन में डेरा डाले हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक खास मकसद से आसिम मुनीर की आर्मी ने अपने पायलटों को बीजिंग भेजा है।

यह पायलट चीन के पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एफसी-31 ग्रेफेलकॉन को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं।

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट्स की मानें तो कुछ महीनों के अंदर यह विमान पाकिस्तान की वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। यह कदम हालिया भारत-पाक टकराव के कुछ हफ्तों

बाद सामने आया है, जिसने भारत के कान भी खड़े कर दिए हैं। भारत के पास ब्रह्मोस जैसे हथियार हैं। अगर पाकिस्तान ने सीमा पर कोई हिमाकत की तो भारत ब्रह्मोस से इन 5वीं पीढ़ी के विमानों को चकनाचूर कर सकता है। अरब सागर में इनके टुकड़े मिलेंगे।

भारत के पास फिलहाल कोई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। भारत इस दिशा में काम कर रहा है और एएमसीए नामक स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, जिसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की संभावना है। अभी तक भारत ने किसी अन्य देश से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

संक्षिप्त समाचार

14 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने डिनो को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया

मुंबई।

मीठी नदी सफाई घोटाला को लेकर बालीवुड अभिनेता डिनो मोरिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शुक्रवार को 14 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिनो को समन भेजा है। उन्हें अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले करोड़ों रुपयों के गबन से संबंधित मामले में फंसे डिनो के बांद्रा स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी, जो करीब 14 घंटे तक चली। ईडी ने मुंबई और कोच्चि में 15 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें डिनो के भाई सैंटिनो, ठेकेदारों और बीएमसी अधिकारियों के परिसर शामिल थे। जानकारी के अनुसार, डिनो के अलावा बीएमसी के सहायक अभियंता प्रशांत रामुगडे सहित अन्य के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इसी मामले में अभिनेता 28 मई को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। अधिकारियों ने अभिनेता से लगभग सात घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाबा महाकाल के दर्शन किए

पत्नी मृदुला प्रधान संग बाबा भस्म आरती में हिस्सा लिया

उज्जैन।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान महाकाल से देश की समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। धर्मेंद्र प्रधान का महाकालेश्वर मंदिर में आगमन सुबह तड़के हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी मृदुला प्रधान संग बाबा भस्म आरती में हिस्सा लिया। पूजन का कार्य मंदिर के पुजारी जितेंद्र शर्मा ने संपन्न करवाया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा को पूर्ण किया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया। समिति के सदस्य आशीष दुबे और अभिषेक शर्मा ने उनका सत्कार किया। उन्हें मंदिर की ओर से प्रसाद, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्वागत के दौरान समिति ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मंदिर की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक महत्व के बारे में भी अवगत कराया।इस दौरान उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रबंधन की भी सराहना की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से वे स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। उज्जैन देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है और यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। महाकालेश्वर मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

बिहार में बीजेपी नहीं दे सकी सीएम चेहरा....इसका फायदा चिराग पासवान उठा रहे

बीजेपी के नेताओं का मानना, नीतिश का चेहरा वोट लाता है

पटना।

बिहार की राजनीति में इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की खूब चर्चा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे चुनाव लड़ने वाले है। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी लोजपा (राम विलास) के कई नेता उन्हें विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता रहे है। इसके बाद से बिहार का सियासी गलियारा कयासों का बाजार गर्म है। बिहार की सत्तारूढ़ भाजपा और जेडीयू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। भाजपा नेतृत्व की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद लोजपा के हिस्से में गई अपनी सीटों में से किसी पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग स्वतंत्र हैं। चिराग के सार्वजनिक बयान तब आए हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोधी लगातार कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा के बाद वे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले है। इसके लिए उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा है कि भाजपा नेता ने माना हैं कि चिराग में अपनी पार्टी के पारंपरिक आधार से परे स्वीकार्यता वाले नेता बनने की क्षमता है। बिहार के एक वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद ने कहा, वह सिर्फ 4 प्रतिशत वोट वाले पासवानों के नेता बनकर खुद को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें अपना जनाधार बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने पत्ते खेल रहे हैं। बिहार भाजपा नेताओं का एक बड़ा गुट ने मानता हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी के लिए चेहरा तैयार करने में विफल रहा और इस विफलता ने चिराग को मौका दे दिया। उन्होंने कहा, ÷चिराग बार-बार यह कह रहे हैं कि वह बिहार जा सकते हैं और सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह दर्शाता है कि वे बिहार की राजनीति में अगले नीतीश बनना चाहते हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717